

नवाभारत



5

59 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

4

भारत में लगेंगे बड़े एआई डाटा सेंटरस

9

भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों को मजबूती

8

खेल मंत्री ने स्वर्ण पदक विजेताओं को किया सम्मानित

दतिया हार की हुई समीक्षा

मुख्यमंत्री निवास में भितरघात के सबूत पेश, पूरी जिला कार्यकारिणी हुई भंग

भोपाल/दतिया, 4 अगस्त. दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री निवास में मंगलवार को आयोजित अहम समीक्षा बैठक में हार के कारणों पर गहन मंथन किया गया. बैठक समाप्त होने के बाद बाहर निकले मंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मीडिया से दूरी बनाने नजर आए. किसी भी नेता ने कैमरे के सामने प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि उनके चेहरों पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी.

सूत्रों के मुताबिक बैठक में दतिया उपचुनाव के प्रभारी आशुतोष तिवारी ने चुनावी हार के कारणों का विस्तृत ब्यौरा रखा. बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के भीतर हुए कथित भितरघात से जुड़े कुछ सबूत भी बैठक में प्रस्तुत किए, जिस पर गंभीर चर्चा हुई. विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो हार की जवाबदेही तय करने की



प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है. इसी क्रम में दतिया भाजपा जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है. संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल और कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है. बैठक में भविष्य की चुनावी रणनीति, संगठन को मजबूत करने और जिम्मेदारी तय करने जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से मंथन हुआ. हालांकि पार्टी की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. ऐसे में कार्यकारिणी भंग होने और संगठनात्मक बदलाव की चर्चाएं फिलहाल सूत्रों के हवाले से ही सामने आ रही हैं.

हार तो हार होती है, चिंतन की जरूरत

नव भारत न्यूज
इंदौर, 4 अगस्त. प्रदेश के दतिया उपचुनाव पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरे चुनाव की अपेक्षा उपचुनाव का ज्यादा महत्व नहीं रहता है. दतिया उपचुनाव की हार को हल्के में नहीं लिया जा सकता. उन्होंने स्पष्ट कहा कि 'हार तो हार होती है और जीत, जीत होती है'.



विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को इस हार पर चिंतन करने की जरूरत है. पार्टी को उपचुनाव के परिणामों और हार के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए. विजयवर्गीय ने बिहार की बांकीपुर सीट पर भाजपा की हार के संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि वह स्वयं बिहार चुनाव

परिणामों की समीक्षा के लिए समिति गठित

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणामों की समीक्षा के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति में प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे और वरिष्ठ नेता अबाराम कराड़ा को सदस्य बनाया गया है. समिति चुनाव से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर दतिया उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन और परिणाम के कारणों का विस्तृत विश्लेषण करेगी. इसके तहत चुनावी रणनीति, संगठनात्मक गतिविधियों और जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति सहित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाएगी.

कर्नाटक कांग्रेस में बगावत सीएम की विधायकों को चेतावनी

- इस्तीफा देंगे तो तुरंत मंजूर होगा: शिवकुमार की दो टूट
- मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस में बढ़ी नाराजगी



बेंगलुरु, 4 अगस्त. कर्नाटक में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के भीतर उभरे असंतोष के बीच मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने नाराज विधायकों को कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीति में इस्तीफा देना किसी का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन यदि कोई विधायक इस्तीफा देता है तो उसे रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा, अगर पार्टी है तो सब कुछ है. पार्टी से बड़ा कुछ

अब दिल्ली से दमन डायरेक्ट उड़ान

90 घरेलू शहरों से जुड़ा आईजीआई, प्रतिदिन 1,050 से अधिक फ्लाइट

नई दिल्ली, 4 अगस्त. राजधानी दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश दमन के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू होने के साथ ही इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एक नई उपलब्धि हासिल की है.



► पश्चिमी भारत के औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगा लाभ

दमन अपने समुद्र तटों, पुर्तगाली स्थापत्य, धार्मिक स्थलों और आतिथ्य उद्योग के कारण प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है. सीधी उड़ान शुरू होने से अब पर्यटक कम समय में आसानी से यहां पहुंच सकेंगे. इस नई कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ पश्चिमी भारत के औद्योगिक क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है.

नई उड़ान सेवा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव केंद्रशासित प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी.

इससे न केवल आम यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा.

ग्वालियर में 1.63 करोड़ की साइबर ठगी

ग्वालियर. बहोड़ापुर इलाके में ऑटोमोबाइल कारोबारी मनीष जैन के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग और बड़े मुनाफे के नाम पर 1.63 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हो गई। ठगों ने कारोबारी को सेबी और बैंक के नाम का झूठा भरोसा दिलाया। बैंक से मिलता-जुलता एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। खुद को बैंक का सीईओ बताने वाले प्रभाव हरिदाशन और अनन्या मेहरा नाम की महिला ने ठगी को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल से 20 जुलाई के बीच कुल 1.86 करोड़ रुपये जमा करवाए गए। जब पीड़ित ने पैसे निकालने चाहे, तो टैक्स और चार्ज के नाम पर और पैसे की मांग की गई। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस और साइबर विंग खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई कर रही है.

► गुस्ताखी माफ



देश का पहला टेलीकॉम हब बनेगा ग्वालियर

ग्वालियर टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग जोन को मिला 1550 करोड़ निवेश प्रस्ताव

भोपाल, 4 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर में विकसित हो रहा टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग जोन निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है. मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग जोन के लिए 1550 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इससे लगभग 3600 रोजगार के अवसर बनेंगे.



इन कंपनियों ने दिखाई निवेश में रुचि

मुंबई बैठक में एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स ने 700 करोड़, अनंत सिस्टम्स ने 400 करोड़, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 200 करोड़, वीएनटी ने 150 करोड़ और टेसकॉम ने 100 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है. इन परियोजनाओं से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से ग्वालियर में देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है. उद्योग अनुकूल नीतियों और पारदर्शी व्यवस्था के कारण मध्यप्रदेश में लगातार बड़े निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि लगभग 170 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह टेलीकॉम जोन दूरसंचार उपकरण निर्माण, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग और इनोवेशन के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा.

अभियान 7 साल में पहली बार भारतीय न्याय प्रणाली में भगोड़े आरोपियों के खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान भी लागू किया

36 देशों से 274 अपराधियों की वापसी



17874 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई अपराधियों की

नई दिल्ली, 4 अगस्त. केंद्र सरकार ने कहा है कि विदेशों में छिपे भगोड़े अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान लगातार मजबूत हो रहा है. गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2019 से 2026 तक कुल 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है.

मोदी के नेतृत्व में भगोड़ों के प्रत्यर्पण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में खुफिया सूचनाओं, आधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित एकीकृत तंत्र विकसित किया गया. गृह मंत्रालय के अनुसार, पहले प्रत्यर्पण प्रक्रिया धीमी, जटिल और कानूनी अड़चनों से घिरी रहती थी. सीमित प्रत्यर्पण संधियां, अधूरे दस्तावेज और एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण कई मामलों

18762 करोड़ की राशि पीड़ितों और संबंधित पक्षों को वापस दिलाई गई

में सफलता नहीं मिल पाती थी. सरकार का दावा है कि 2019 के बाद इस व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, एनआईए संशोधन अधिनियम, यूएपीए संशोधन अधिनियम और नए आपराधिक कानूनों के जरिए कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया. पहली बार भारतीय न्याय प्रणाली में भगोड़े आरोपियों के खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान भी लागू किया गया.

सरकार के मुताबिक, 2019 से 2026 के बीच भगोड़े अपराधियों की संपत्तियां जब्त की गईं, जबकि 18,762 करोड़ की राशि पीड़ितों और संबंधित पक्षों को वापस दिलाई गई. इसी अवधि में इंटरपोल के माध्यम से सैकड़ों रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को गति मिली.

भारत-चीन के बीच सकारात्मक बातचीत

नयी दिल्ली 4 अगस्त. भारत ने चीन के साथ संबंधों के बारे में कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और लोगों के बीच परस्पर संबंध बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन में सोशल मीडिया पर भारत और भारतीय संस्कृति के खिलाफ दुष्प्रचार से संबंधित सवाल पर कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर कैलाश मानसरोवर यात्रा और हवाई संपर्क की बहाली सहित अनेक कदम उठाये जा रहे हैं.



हवा में गुलाटी मारने लगा विमान



300	15	134	एयर इंडिया फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
फीट नीचे गिरी फ्लाइट	यात्री घायल जांच शुरू	यात्री और 8 कू सदस्य सवार थे	

एयर इंडिया ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है. हालांकि, घटना के बाद सामने आई तस्वीरों में विमान के केबिन की छत और

ओवरहेड पैनलों को नुकसान पहुंचा दिखाई दिया. फ्लाइट में मौजूद एक यात्री ने बताया कि उड़ान भरने के करीब डेढ़ घंटे बाद अचानक तेज झटके शुरू हुए. उस समय अधिकांश यात्री सो रहे थे.

कार और बाइक इंश्योरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के नए नियम

नई दिल्ली, 4 अगस्त. सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीडितों के हितों को ध्यान में रखते



अदालत ने निर्देश दिया है कि अब नई कारों के लिए चार वर्ष और नई दोपहिया वाहनों के लिए छह वर्ष का थर्ड-पार्टी मोटर

इंश्योरेंस अनिवार्य होगा. इससे पहले वर्ष 2018 के आदेश के तहत नई कारों के लिए तीन वर्ष और दोपहिया वाहनों के लिए पांच वर्ष का बीमा अनिवार्य था. इस फैसले के बाद नई गाड़ियों की ऑन-रोड कीमत बढ़ने की संभावना है क्योंकि अतिरिक्त एक वर्ष के बीमा का प्रीमियम वाहन खरीदते समय ही देना होगा. यानी वाहन की शुरुआती लागत पहले की तुलना में अधिक होगी.



ई 20 के खिलाफ केजरीवाल का पीएम आवास मार्च, पुलिस ने रोका

- ई 20 पर आप का प्रदर्शन, फिरोजशाह रोड पर हंगामा
- दो लाख से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखीं

नई दिल्ली, 4 अगस्त. आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को ई 20 ईंधन नीति के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को फिरोजशाह रोड पर ही रोक दिया. इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सोरभ भारद्वाज, जैस्मिन शाह और अन्य नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए. आप के अनुसार, प्रदर्शन में करीब 100 नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशभर से दो लाख से अधिक लोगों ने ई20

नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखीं हैं. उनका कहना था कि वे इन पक्षों को स्वयं प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया. केजरीवाल ने दावा किया कि सभी चिट्ठियां पुलिस के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दी गई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहले ही समय मांगा गया था और उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत का अवसर मिलेगा. धरने को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ई 20 नीति आम जनता के हित में नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर व्यापक जन आंदोलन की आवश्यकता है और लोगों से अभियान में जुड़ने की अपील की. वहीं, आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक महीने पहले समय मांगा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.